फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 72 संख्याः 152 प्रभात जयपुर, शनिवार 1 जनवरी, 2022 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Give Me A Hug

Did you ask someone to put ON their mask so that you could recognize them? I know there is a Tic Tok about that. Too close to reality.

Brot Co-Get Buttured

Prevention of Iodine Deficiency

वैज्ञानिकों व मनोवैज्ञानिकों का मानना है, करोना के जाने का समय तो आ गया है

पर लोगों की मनःस्थिति पर उसका असर दशकों तक रहेगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर। ब्रायन पॉटिंगर, जो दक्षिण अफ्रीका के वरिष्ठ पत्रकार तथा वहाँ "सनडे टाइम्स" के पूर्व सम्पादक हैं, कहते हैं कि करोना वायरस महामारी तो देर-सवेर समाप्त प्राय हो जायेगी, लेकिन निकट भविष्य में सारी दुनिया के लोगों की स्थिति में सुधार होना संभव नहीं है, क्योंकि "हिंसक पशु के मुँह खून लग गया है।"

"अ क्रिटिकली नीडेड पर्सपैक्टिव ऑन कोविड" शीर्षक वाली पुस्तक में उन्होंने समझाया है कि, करोना से लड़ने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाए गए तरीकों के कारण अधिकतर देशों में नियंत्रण की जो मानसिकता पैदा हुई, उसके बाद क्यों अब कोविड-19 "समाप्ति के चरण" में है।

पॉटिंगर लिखते हैं "यह एक विडम्बना है कि करोना वायरस से निबटने में हुई जबरदस्त भूलों और गलतियों के बावजूद, सरकारों के विभिन्न अंग तथा डब्ल्यू.एच.ओ. जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ बहुत मजबूत होकर उभर रहे हैं, इसके अलावा, बड़ी फार्मा कम्पनियों तथा टैक्नोलॉजी प्रतिष्ठानों ने तो लोगों पर अकल्पनीय नियंत्रण करने में सरकारों की मदद की ही है।"

- करोना के संक्रमण से बचने के लिये, जो प्रतिबंध आम आदमी पर लगे उसके बाद उसकी प्राइवेसी व आवागमन व मिलने मिलाने की स्वतंत्रता वापस आने में बहुत समय लगेगा।
- इस पर भी काफी मंथन व चिंतन हुआ है कि, आम जनता अपनी यह स्वतंत्रता इतनी आसानी से छोड़ने को क्यों तैयार हो जाती है।
- मनोवैज्ञानिकों का मानना है, सोशल मीडिया के प्रचलन से आम आदमी अकेलापन महसूस करता है, अपने को दोस्त विहीन मानता है तथा अपने कामकाज व रोजगार को अर्थहीन मानता है, जिसका कोई महत्व नहीं है।
- इन व्यक्तिगत चिन्ताओं व कुण्ठाओं के कारण आम आदमी एक "सुपरमैन" के आने का इंतजार करता है, जो इन व्यक्तिगत समस्याओं का हल सुझायेगा।
- इसी मनःस्थिति में व्यक्तिगत कुण्ठाओं का समाधान ढूंढता हुआ आम आदमी अपनी स्वतंत्रताएं त्यागने को भी तैयार हो जाता है।

पॉटिंगर आगे कहते हैं, "महामारी अन्ततोगत्वा समाप्त तो होगी ही, लेकिन बड़ा लम्बा दीर्घकालीन कोविड प्रभाव है, जो हमें लम्बे समय तक तंग करता रहेगा।"

पॉटिंगर का सोच प्रोफेसर मटायस डैसमैट के विचारों से मिलता है, जिन्होंने इस मनोवृत्ति पर लेख लिखा है कि लोग क्यों स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्रता को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं

प्रो. मटायस गेन्ट यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर तथा मास्टर इन स्टेटिस्टिक्स हैं।

सामाजिक मनोविज्ञान के विषय में डिसमैट के विचार, जिसमें राजनैतिक उद्देश्यों या महामारी के लिये व्यापक विचार निर्माण एवं राजनैतिक गतिशीलता पर जोर दिया गया है, बहुत अन्तर्दृष्टि सम्पन्न हैं- ये मुख्यत: अस्तित्व संबंधी चिंताओं का प्रोजेक्शन हैं, जो किसी समाधान की तलाशों में है। इसके कुछ डेटा बताते हैं- खासतौर से युवा आबादी का चौथा हिस्सा, अपने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्ण लॉकडाउन

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर। जहाँ अब बड़ी संख्या में देश लॉकडाउन से दूर हो गये हैं, वहीं चीन अपनी "जीरो कोविड" रणनीति पर दोगुना जोर दे रहा है।

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में

- चीन ने करोना के बढ़ते प्रकोप पर अंकुश लगाने के लिए बड़े शहर शीआन में लॉकडाउन लगाया।

कहा गया है कि, चीन की सरकार के अनुसार, शीआन, जो पश्चिमोत्तर चीन का 1.30 करोड़ आबादी वाला एक प्रमुख शहर है, में 9 दिसम्बर से 29 दिसम्बर के बीच 1,117 संक्रमण रिकॉर्ड किये गये हैं। हालांकि, पश्चिमी देशों की तुलना में यह काफी छोटी संख्या है, लेकिन इस महामारी की शुरूआत से लेकर अब तक, चीन के किसी भी शहर के संक्रमण-केसों की यह सबसे बड़ी संख्या है। इन केसों की संख्या को देखते हुये, अधिकारियों ने पिछले सप्ताह इस शहर में लॉकडाउन लगा दिया, सारे स्कूल तथा अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कर दिये तथा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना बहुत खतरनाक'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर। संसद के शीतकालीन सत्र में इस माह की शुरूआत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के संशोधनों के पारित होने के बाद करीब सौ से अधिक वरिष्ठ नौकरशाहों ने मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने की केन्द्र सरकार की योजना पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च स्तर पर "कठोर न्यायिक हस्तक्षेप" की मांग की है।

उन्होंने आशंका जताई कि मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड डेटा से लिंक करने से लाखों वोटर अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं क्योंकि जब उन्हें पोलिंग बूथों पर मतदाता सूचियों में अपने नाम गायब मिलेंगे तब उन्हें इस कदम की भयावहता का एहसास होगा।

इन लोगों ने इस कदम को "त्रुटिपूर्ण, विधिक रूप से गलत, कपटपूर्ण और सरकार द्वारा दुरूपयोग किए जाने योग्य" बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वो हस्तक्षेप करे, क्योंकि, कहीं ऐसा ना हो कि इस लिंक का आगामी विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल किया जाए, मतदाताओं की पहचान का खुलासा करने के लिए, जिसके कारण, हो सकता है कि, मतदाता मतदान करने से परहेज करें।"

इस आधार पर कि, मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण जरूरी है, सरकार ने संसद में और उसके बाहर

- सौ से अधिक वरिष्ठ आई.ए.एस. स्तर के अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय से अपील की कि, इसे रोकने में मदद करें।
- इन लोगों का मानना है कि, आधार कार्ड व वोटर पहचान पत्र के लिंकेज से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता व प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा।

विरोध प्रदर्शन होने के बावजूद इलैक्शन आइडैन्टिटी प्रोटैक्शन बिल में संशोधन प्रस्तावित किए।

सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने, कुछ वर्ष पूर्व गठित "कॉन्स्टिट्यूश्नल कन्डकट" के प्लेटफार्म से एक स्पष्ट बयान जारी करते हुए कहा कि, आधार वैरिफिकेशन की अनिवार्यता, यदि स्वैच्छिक भी है, तब भी, रजिस्टर्ड वोटर के दृष्टिकोण से इसका तात्पर्य यह हुआ कि, आईडैन्टिटी और एड्रैस वैरिफिकेशन के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र को वोटिंग लिस्ट से जोड़ने से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता प्रभावित होगी, और समूची मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होगा।

बयान में रेखांकित किया गया कि, डेटा प्रोटैक्शन बिल का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस बी.एन. कृष्णा ने इस प्रकार की लिंकिंग को "सर्वाधिक खतरनाक स्थिति" बताते हुए इसकी भर्त्सना की थी।

बयान में चेतावनी दी गई कि, महानरेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे सरकारी कार्यक्रमों के डेटा बेस पंजीकरणों के शुद्धिकरण के लिए आधार के उपयोग का परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे लोग इसके पात्र नहीं रहे क्योंकि बिना किसी नोटिस के उनके नामों को मनमाने ढंग से सिस्टम से हटा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मोदी असहाय क्यों'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर। कांग्रेस ने चीन की हर प्रकार की आक्रामकता

- कांग्रेस ने सवाल उठाया कि, चीन लगातार अरूणाचल के क्षेत्रों को नए नाम दे रहा है और मोदी चुप क्यों हैं।

पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल खड़े किये तथा कहा कि चीन ने अरूणाचल के 15 स्थानों के नाम बदलकर दूसरे नाम रख दिये हैं तथा उसने भारतीय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अपने समर्थकों को मंत्री बनाने में सफल रहे पायलट लेकिन डेढ़ साल से खुद रहे खाली हाथ

क्या 2022 में कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट की राजनीतिक भूमिका तय करके राजस्थान में राजनीतिक टकराव को समाप्त करेगा?

जयपुर, 31 जनवरी (का.प्र.)। राजस्थान में जुलाई 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बाद सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद गंवाना पड़ा था। उन्हीं के साथ उनके समर्थक मंत्रियों रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को भी पद से हटा दिया गया था। इतना ही नहीं उनके समर्थकों ने जुलाई 2020 में सचिन पायलट को हटाए जाने के बाद इस्तीफे दिए थे, जिनमें सेवादल के अध्यक्ष राकेश पारीक और एनएसयूआई के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया प्रमुख हैं। वहीं युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे मुकेश भाकर को भी उस समय हटा दिया गया था।

इन बातों को डेढ़ साल पूरा हो चुका है, लेकिन हाल ही हुए मंत्रिमंडल विस्तार में रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह फिर मंत्री बनाए जा चुके हैं और पायलट कैंप के तीन अन्य चेहरे भी मंत्री बन चुके हैं। लेकिन सेवादल, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने वाले नेताओं को अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। हालांकि इनमें से दो, राकेश पारीक और मुकेश भाकर पार्टी के विधायक है। किन्तु बड़ा सवाल यह है कि सचिन पायलट के 4 समर्थकों को मंत्री बनाए जाने के बाद क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता समाप्त हो चुकी है? इसका जवाब फिलहाल आना बाकी है और 2021 की समाप्ति के साथ यह भी तय हो चुका है कि फिलहाल सचिन पायलट खाली हाथ है। हालांकि इस दौरान उन्होंने राजस्थान में जहां भी दौरे किए,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोटपूतली में धरने के नवें दिन महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला

महिलाओं का कहना है कि, जब रहने के लिए छत ही नहीं रहेगी तो सड़कों पर तो उतरना ही था

कोटपूतली, 31 दिसम्बर (निसं)। कोटपूतली में मास्टर प्लान के अनुरूप मुख्य सड़कों को चौड़ा करने को लेकर स्थानीय नगरपालिका मंडल कि कार्यवाही के खिलाफ नगर व्यापार महासंघ के बैनर तले पीड़ित व्यापारियों का धरना शुक्रवार को लगातार नौवें दिन भी पुरानी नगरपालिका तिराहे पर यादव के खिलाफ जमकर नारे बाजी की। दरअसल महिलाओं का इस तरह खुले मंच पर आना और आन्दोलन की राह पकड़ना लाजमी है।

महिलाओं को कहना है कि जब रहने के लिए छत नहीं बचेगी, खाने के लिए रोजगार नहीं बचेगा तो आखिर सड़क पर उतरने के अलावा उनके पास साफ नहीं है। सड़कों को चौड़ा करने को लेकर मुख्य चौराहे से नगरपालिका तिराहे तक डिवाईडर को आधार मान कर चिन्हीकरण किया गया है, जबकि सरदार स्कूल के सामने बिना कोई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- कोटपूतली का नगर व्यापार महासंघ शहर के मास्टर प्लान के अनुरूप मुख्य सड़कों को चौड़ा करने का विरोध कर रहा है। उनका आरोप है कि नगर पालिका की कार्यवाही भेदभावपूर्ण है।
- नगर व्यापार महासंघ का आरोप है कि उन्हें बिना कोई नोटिस दिए उनके भवन ध्वस्त किए जा रहे हैं।

बदस्तूर जारी रहा।

कस्बे में विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले केवल व्यापारी वर्ग ही धरना प्रदर्शन कर रहा था वहीं अब महिला शक्ति भी इस आन्दोलन का हिस्सा बन गई हैं। शुक्रवार को सरदार स्कूल के सामने रहने वाले मकानों से महिलाएं भी निकल कर धरना स्थल पहुंचीं, जहां उन्होंने व कार्यवाही धरनार्थियों ने पालिका अधिशाषी अधिकारी व गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह चारा ही क्या बचा है। महिलाओं का कहना है कि उनका परिवार कई पीढ़ियों से सरदार स्कूल के सामने अपनी संरचनाओं में रहता आया है, किन्तु राजनैतिक द्वेष के चलते पालिका प्रशासन ना केवल बिना मुआवजा दिए उनकी रोजी-रोटी छीन रहा है, बल्कि उनके सिर की छत भी छीनी जा रही है।

आरोप है कि पालिका अधिशाषी अधिकारी द्वारा मास्टर प्लान के तहत की जाने वाली कार्यवाही को लेकर मंशा

पहले जिला अध्यक्ष बना दिया, अब राजनीतिक नियुक्ति भी उन्हीं लोगों को दे दी

जयपुर, 31 दिसम्बर (का.प्र.)। कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2021 के अंतिम दिन राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां शुरू कर करते हुए सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 10 जिला उपाध्यक्ष बनाए हैं।

जिन लोगों को 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है, उनमें से 10 लोग वह है जो हाल ही जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। यानी कि कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्ति देने के बजाय एक व्यक्ति दो पद के सिद्धांत पर काम किया गया है।

जिन लोगों को यह मौका मिला है इनमें अलवर के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, बारां के जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा, बाड़मेर के जिला अध्यक्ष फतेह खान, दौसा के जिलाध्यक्ष रामजीलाल ओढ़, जैसलमेर के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर, झालावाड़ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जोधपुर के जिला अध्यक्ष सलीम खान ,नागौर के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत, राजसमंद के जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ और सीकर की जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला शामिल हैं।

- जिला कांग्रेस के 10 अध्यक्षों को बनाया 20 सूत्री कार्यक्रम का जिला उपाध्यक्ष।

इन नियुक्तियों से यह संकेत भी मिल रहा है कि आने वाले दिनों में भी जो राजनीतिक नियुक्तियां संभावित है, उनमें भी विधायक और पूर्व विधायकों सहित चुनाव लड़ने वाले नेताओं को ज्यादा मौके मिलने वाले हैं। या फिर उन लोगों को मौका मिलेगा, जो पहले भी राजनीतिक नियुक्तियों से नवाजे जा चुके हैं।